Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

एनईपी 2020 का अध्ययन : मुद्दे, दृष्टिकोण, चुनौतियाँ, अवसर और आलोचना

मो. जिमी, शोधार्थी, पी जी डिपार्टमेंट ऑफ़ उर्दू, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर (बिहार)

ईमेल : jimmymd786@gmail.com

शोध सार

एक अच्छी तरह से परिभाषित शिक्षा नीति और भविष्य स्कूल और कॉलेज स्तर पर देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। विभिन्न देश संस्कृति और परंपराओं का उचित सम्मान करते हुए विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करते हैं और इसे कार्यान्वित करने के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा स्तरों पर अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न चरण अपनाते हैं। 29 जुलाई, 2020 को भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), भारत की नई शिक्षा प्रणाली के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करती है। नई नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेती है। यह नीति भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस नीति का लक्ष्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नीति जारी होने के तुरंत बाद, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शिक्षण की पद्धति को अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में नहीं बदला जाएगा। एनईपी में भाषा नीति के आवेदन पर स्कूलों को निर्णय लेना है। भारत में शिक्षा संबंधित सूची नीति 2020 का अध्ययन है। 2022 तक भारत के सभी स्कूलों में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए।

संकेत शब्द

उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी-2020, अवलोकन और विश्लेषण, एनईपी 2020 के लिए कार्यान्वयन रणनीतियाँ, तरीके, चुनौतियाँ, अवसर

पृष्ठभूमि

एनईपी 2020 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है। जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जून 2017 में, एनईपी का मसौदा 2019 में भारतीय अंतरिक्ष

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व मुख्य कार्यकारी कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाले एक पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2019 के लिए नई शिक्षा नीति रूपरेखा (डीएनईपी) बाद में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी की गई, जिसके बाद कई सार्वजनिक सुनवाई हुई। T74 ड्राफ्ट NEP में 484 पृष्ठ थे। विभाग नीति ढांचे के निर्माण में एक मजबूत परामर्श प्रक्रिया से गुजरा है: "2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), 676 जिलों के 2 लाख से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।"

परिचय

शिक्षा में परिवर्तन के तेजी से बढ़ते स्वतंत्र देश के रूप में भारत में वर्तमान में लगभग 845 विश्वविद्यालय और लगभग 40,000 उच्च शिक्षा संस्थान (एचआईई) हैं, जो इन विश्वविद्यालयों से जुड़े देश में कुल विविधता और कई छोटे एचईआई को दर्शाते हैं। यह पाया गया है कि इनमें से 40% से अधिक छोटे संस्थान बहु-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा प्रणाली के अपेक्षित परिवर्तन के विरुद्ध मेरे लिए एकल प्रणाली का उपयोग करते हैं जो 21वीं सदी में शैक्षिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह भी नोट किया गया कि 20% से अधिक कॉलेजों में सालाना 100 से कम छात्रों का नामांकन होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना असंभव हो जाता है और केवल 4% कॉलेजों में क्षेत्रीय असमानता और शिक्षा के स्तर के कारण प्रति वर्ष 3,000 से अधिक छात्रों का नामांकन होता है । वे देते हैं। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली (एचई) के पतन के लिए पाए जाने वाले कुछ कारण इस प्रकार हैं: यह अनुमान लगाया गया है कि भारत 2030-2032 में लगभग दस अरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। यह स्पष्ट है कि दस अरब अर्थव्यवस्थाएँ सूचना के स्रोतों से संचालित होंगी, न कि प्राकृतिक संसाधनों से। भारत के शिक्षा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पेश करके इसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। यह भारत को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति का उपयोग करने के प्रधान मंत्री के नवीनतम आह्वान के अनुरूप है। नई लॉन्च की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक भारत-केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम का दृष्टिकोण है जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को समान और जीवंत ज्ञान वाले समाज में बदलने में सीधे योगदान देता है।

एनईपी 2020 के मुद्दे

- विभिन्न विषयों में छात्रों का प्रारंभिक वितरण।

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

- एचई तक पहुंच की कमी, विशेष रूप से सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) केवल 25% है।

- एचई में नए काम करने के लिए शिक्षकों और संस्थागत स्वतंत्रता की कमी छात्रों को अधिक आकर्षित करती है।

- अपर्याप्त नौकरी प्रबंधन प्रथाएं और संस्थागत नेताओं के साथ बुद्धि की उन्नति।

- कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचार का अभाव।

- उच्च शिक्षा संस्थानों में शासन और नेतृत्व का निम्न स्तर।

- एक भ्रष्ट नियंत्रण प्रणाली जो बेहतर, नवीन संस्थानों पर दबाव डालते हुए फर्जी कॉलेजों को पनपने की अनुमति देती है।

एनईपी 2020 के दृष्टिकोण

1. पाठ्यचर्या और सामग्री

एनईपी का लक्ष्य 10 + 2 भवन से 5 + 3 + 3 + 4 भवन में संक्रमण शुरू करना है, जहां प्रारंभिक बचपन की शिक्षा औपचारिक शिक्षा का हिस्सा होगी। इसके अलावा, एनईपी 2020 आलोचनात्मक सोच के लिए जगह बनाने के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री को कम करने और बदले में, उनमें शामिल 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने पर केंद्रित है। इसलिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण के सभी पहलुओं को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने की चुनौतियों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप पाठ्यक्रम को संशोधित करना शामिल है। साथ ही, शिक्षकों को पठन सामग्री रूब्रिक पर पुनर्विचार करने और पाठ्यपुस्तकों को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।

2. शिक्षक उपलब्धता एवं प्रशिक्षण

इस नीति का उद्देश्य स्कूली पाठ्यक्रम को नया स्वरूप देना है। हालाँकि, पाठ्यक्रम के प्रभावी होने के लिए, स्कूलों और संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और शिक्षण की जरूरतों को समझने की आवश्यकता है ताकि नई शिक्षा प्रणाली में एक सुचारु परिवर्तन हो सके। इसके अलावा, उन्हें

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

युवा लोगों में पारस्परिक, आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और निर्णय लेने के कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक- केंद्रित पढ़ने से छात्र - केंद्रित पढ़ने की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। अध्ययन से पता चलता है कि 2030 तक भारत के K-12 स्कूलों में 250 मिलियन से अधिक छात्रों का नामांकन होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि छात्रों की इस बढ़ती संख्या से निपटने के लिए हमें लगभग 7 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता है। चूँकि शिक्षण भारत में सबसे कम वेतन वाली नौकरियों में से एक है, अनुभवात्मक शिक्षा और मन-केंद्रित शिक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जब तक शिक्षकों के वेतन समीक्षा की समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक एनईपी 2020 का कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती होगी।

3. प्रौद्योगिकी

एनईपी 2020 युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी लाभों के उपयोग पर जोर देता है। हालाँकि, शारीरिक शिक्षा और प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए डिजिटल कक्षाओं, दूरस्थ पेशेवर-आधारित शिक्षण मॉडल, एआर / वीआर उपकरण जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अधिकांश स्कूलों में सही सेटअप नहीं है। इन उपकरणों का समर्थन करें. साथ ही, डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ी लागत देश भर के सभी स्कूलों के लिए कम महंगी हो सकती है। इसके अलावा, देश के ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट लगभग नगण्य है , डिजिटल शिक्षण उपकरणों का उपयोग करना सवाल से बाहर है। इसलिए, सरकार को बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए जो सभी क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा।

4. परीक्षण भवन

एनईपी संक्षिप्त मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित है। मूल्यांकन कार्यक्रम को संशोधित करने का प्राथमिक उद्देश्य सीखने के परिणामों की निरंतर ट्रैकिंग को बढ़ावा देना है। हालाँकि, आगे के परीक्षण के लिए स्कूलों और शिक्षकों को नई मूल्यांकन विधियों और असाइनमेंट को अपनाने की आवश्यकता है। इन दृष्टिकोणों के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 15 लाख भारतीय स्कूलों में से 75 प्रतिशत स्कूल सरकारी हैं। शेष 400,000 निजी स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत 'निजी स्कूल' हैं । इसलिए, सतत मूल्यांकन रूपरेखा भेजना इन स्कूलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

एनईपी 2020 की चुनौतियाँ

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

1. साप्ताहिक विश्वविद्यालय खोलना एक अत्यंत कठिन कार्य है

भारत में आज पूरे देश में लगभग 1,000 विश्वविद्यालय हैं। 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल अनुपात नामांकन को दोगुना करना, जो नीति के घोषित लक्ष्यों में से एक है, का मतलब होगा कि हमें अगले 15 वर्षों तक हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय खोलना होगा । निरंतर आधार पर प्रत्येक सप्ताह एक विश्वविद्यालय खोलना निस्संदेह सबसे बड़ी चुनौती है।

2. हमारी स्कूल प्रणाली की परिवर्तन योजनाओं में कीमतें भी बहुत चिंताजनक हैं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य उन 2 मिलियन बच्चों को स्कूल प्रणाली में वापस लाना है जो वर्तमान में स्कूल से बाहर हैं। आप इसे जिस भी तरीके से देखें, 15 वर्षों में इसे हासिल करने के लिए प्रत्येक सप्ताह लगभग 50 स्कूलों को निलंबित करना होगा।

3.कोविड काल में फंडिंग एक बड़ी चुनौती है

सहायक दृष्टिकोण से, यह कमज़ोरों के लिए कोई चुनौती नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% से बढ़कर 6% होने का अनुमान है, जो प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह पैसा देश भर में स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण, शिक्षकों और प्रोफेसरों की नियुक्ति और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता प्रदान करने जैसे संचालन खर्चों पर खर्च किया जाएगा। जो बात चीजों को और भी कठिन बनाती है वह यह है कि यह नीति ऐसे समय में आई है जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 से संबंधित बंदी से अभिभूत है , सरकारी कर में कटौती बहुत कम थी, और कोविड से पहले भी फंडिंग की कमी अधिक थी।

4. वर्तमान फोकस मानव हत्या दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक स्थिरता पर है

सरकारी खजाने में कठिनाइयों के बावजूद, अर्थशास्त्री सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक के बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पैकेज की तलाश में हैं।

5. बड़ी संख्या में योग्य शिक्षक तैयार करने की आवश्यकता

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

स्कूली शिक्षा में, नीति का लक्ष्य पाठ्यक्रम संरचना को एक बहुत ही स्वीकार्य कदम के रूप में नया स्वरूप देना है। लेकिन इस पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो प्रशिक्षित हों और जो शिक्षण आवश्यकताओं को समझते हों। कई पाठ्यक्रम परिवर्तनों के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों की सोच में भी बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है।

6. उच्च शिक्षा आवश्यकताएँ जिनमें सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए अनुशासन शामिल हैं

उच्च शिक्षा में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुशासनात्मक शिक्षा पर फोकस एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। विश्वविद्यालय, विशेष रूप से भारत में, दशकों से विभागों द्वारा चुपचाप चलाये जाते रहे हैं। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और दायरे में सुधार के लिए कई पहल शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर इस अध्ययन के उद्देश्य हैं

(1) नव अपनाई गई उच्च शिक्षा प्रणाली (एनईपी 2020) की नीतियों पर प्रकाश डालना और उनकी संक्षिप्त समीक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तुलना वर्तमान में भारत में अपनाई गई नीति से करें।

(3) नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 में नवाचारों की पहचान करना।

(4) भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पर एनईपी 2020 के प्रभावों की भविष्यवाणी।

(5) एनईपी 2020 उच्च शिक्षा नीतियों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

(6) अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनईपी 2020 का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आगे के विकास के लिए सिफारिशें।

लक्ष्य और समयसीमा

यहां नीति के प्रमुख लक्ष्य और कुछ के लिए निर्धारित समय-सीमाएं दी गई हैं:

1. पूरी नीति 2040 तक लागू हो जाएगी।

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

2. 2030 तक प्री-स्कूल से दूसरे स्तर तक कुल नामांकन दर का 100%।

3. शिक्षकों को 2030 तक परीक्षा परिवर्तन के लिए तैयार किया जाएगा।

4. सार्वजनिक और निजी स्कूलों में सीखने का मानक स्तर।

5. लक्ष्य सभी ग्रेड 3 शिक्षार्थियों के लिए बुनियादी संख्यात्मकता और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना है।

6. 2030 तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करना।

7. 2025 तक कम से कम 50% छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

एनईपी 2020 के अवसर

नई शिक्षा नीति एनईपी - 1986 के अधूरे एजेंडे से शुरू होती है। एनईपी - 1986 एक बहुत ही अलग भारत में निहित थी।

पिछले कुछ वर्षों में पहुंच और समानता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लगभग सार्वभौमिक स्तर और उसके बाद उच्च शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि (जीईआर: 26.3%) हासिल की गई है। हालाँकि, सार्वजनिक स्कूल प्रणालियों में सीखने की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है, जिसके बाद अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग का पलायन हुआ है। इससे जवाबदेही तंत्र भी कमजोर हुआ। सीखने पर खराब रिटर्न के बावजूद, सार्वजनिक प्रणालियों में वेतन-संरचना में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है।

1. स्कूली शिक्षा

10+2 भवन का 5+3+3+4 में नवीनीकरण। प्री-स्कूल वर्षों को कवर करने के लिए एक नई शिक्षण संरचना और पाठ्यक्रम। यह ठीक ही है क्योंकि शिक्षा नीति के दस्तावेज़ों में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है और इस पर अनौपचारिक ढंग से चर्चा की जा रही है। एनसीईआरटी एक नए ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नीति लघु और दीर्घकालिक कार्यक्रमों के माध्यम से आंगनवाड़ी प्रशिक्षकों के विकास और प्रशिक्षण को भी गहरा बनाती है। ईसीसीई के गठन और वितरण को वैध बनाना एक अच्छा लक्ष्य है। बुनियादी गणित और ग्रेड 3 सीखने पर ध्यान दें।

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) इसे सुदृढ़ करेगा, और इसे एक अलग राष्ट्रीय सेवा के माध्यम से यंत्रवत् करेगा। देश भर में पुस्तकालयों को विकसित करने और बच्चों में पढ़ने के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाई गई है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हैं। यदि इसे सार्वजनिक शिक्षा नीति द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है, तो यह समावेशी है। अंडे अभी भी एक विवादास्पद नीतिगत मुद्दा हैं, नीति किसी भी अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए इसे स्पष्ट और स्पष्ट बनाती है। हालाँकि, सभी प्रकार के संघर्षों से बचने के लिए यह अनुभाग हमेशा लचीला है। आधी-अधूरी समझ और अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य और 'गुणवत्ता' वाले पिता के लिए बाजार के दबाव ने इस लचीलेपन को जन्म दिया होगा। यह नीति किसी एक भाषा को दूसरी भाषा पर थोपने/लागू करने/वरीयता नहीं देती और बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। यह दूसरे स्तर पर विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की भी सिफारिश करता है: कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। इसे अब तक तकनीकी दस्तावेज़ों में सार्वजनिक डोमेन के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। हालाँकि बाद की श्रेणियाँ वर्ग, जातीयता, विकलांगता, ट्रांसजेंडर लोगों जैसी श्रेणियों पर प्रकाश डालती हैं और छोटे शब्दों के क्षणिक संकेतक हैं। प्रौद्योगिकी की आलोचना को छोड़कर, नीति इन समूहों पर पंजीकरण और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयासों पर विचार करती है। परख, एक नया निकाय जो एनएएस (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) और एसएएस (राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण) जैसे परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

परख सीखने के स्थानों की खोज और विभिन्न लक्ष्यों और सेवा कार्यक्रमों के लिए लक्षित समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

2. उच्च शिक्षा

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में क्या हुआ है, साथ ही शीर्ष विश्वविद्यालयों की हालिया बहस के संदर्भ में नीति को देखना महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता का लगातार ह्रास किया जा रहा है। भारत के अग्रणी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से एक में प्रस्तुत की गई विकृत राज्य हिंसा बहुत पहले नहीं हुई थी। शिक्षण, सीखने, अनुसंधान और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वविद्यालय के नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियाँ सबसे अच्छे सरकारी उपकरण हैं। हालाँकि यह दस्तावेज़ विनियामक स्वतंत्रता पर जोर देता है, लेकिन यदि दस्तावेज़ वित्तीय स्वतंत्रता भी बताता है तो यह मुश्किल हो सकता है।

इस 'कल्पनाशील' स्वायत्तता को यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) और एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के प्रतिस्थापन द्वारा माना जाता है। नई संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नौकरी पृथक्करण और नौकरी पृथक्करण के विचार पर आधारित है।

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

यह नीति शिक्षा की बिक्री का भी विरोध करती है। हालाँकि, वही चौड़ाई विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति देती है। भारतीय प्रदाताओं द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है। यदि विचार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का था, तो यह समझ में आता है। हालाँकि, बयान प्रस्तुत करना नहीं है।

भविष्य के पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना समझ में आता है, और संस्थानों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित एक अलग निकाय एक आवश्यक दृष्टिकोण है।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक और अच्छा विचार है। हालाँकि, अगर ये अंतराल वैचारिक एजेंडे से प्रेरित लोगों द्वारा भरे जाते हैं, तो बहुत कम उम्मीद की जा सकती है।

भारतीय विश्वविद्यालयों को दुनिया में कहीं और कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी - खाड़ी बाजारों में इसके विकास की काफी संभावनाएं हैं। भारतीय प्रवासियों को उच्च शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। एनईपी 2020 की आलोचना

यहां उन आलोचनाओं की सूची दी गई है जो एनईपी 2020 के खिलाफ लगाई गई हैं , या जो लगाई जा सकती हैं। एनईपी ने संसदीय निरीक्षण, चर्चा और जांच को दरकिनार कर दिया। यह देखते हुए कि इसे उस समय लाया गया है जब संसद COVID-19 के कारण काम नहीं कर रही है, यह एक जल्दबाजी वाला दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना प्रतीत होता है। ये भी पहली बार नहीं हुआ है. पिछले 6 वर्षों में संसद सदस्यों को बार-बार महत्वपूर्ण चर्चाओं से बाहर रखा गया है, जिससे उन्हें नीतियों की आलोचनात्मक जांच करने या अन्यथा अपने विचार व्यक्त करने और संशोधनों का सुझाव देने से रोका गया है।

नीति एक दृष्टि दस्तावेज है जो समाज के सबसे निचले तबके को शामिल करने में विफल रहती है और गरीबों, महिलाओं और जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुत कम या कोई राहत नहीं देती है, क्योंकि यह शिक्षा तक पहुंच की प्रमुख चिंताओं पर पर्दा डालती है जो लंबे समय से चली आ रही है। . इस भव्य दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यापक रोडमैप और सुसंगत कार्यान्वयन रणनीति नहीं है।

इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कई मील के पत्थर और वित्त के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। उदाहरण के लिए, इस पंक्ति को लें: "केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।" ऐसी कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं है जो सरकार को जवाबदेह ठहरा सके।

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

3. त्रिभाषा सूत्र

हालाँकि नीति इस प्रावधान को बाध्य नहीं करती है, लेकिन इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि छात्रों/शिक्षकों/स्कूलों के पास बहुत कम विकल्प और लचीलापन बचता है। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है उससे हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की केंद्र सरकार की मंशा के खिलाफ 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद आना स्वाभाविक है। दक्षिण के राजनीतिक दल इसे गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी थोपने के मोदी सरकार के कदम के रूप में देख रहे हैं। बेशक, यह इस तथ्य के बावजूद है कि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपेगा और इस पर अंतिम निर्णय राज्य पर ही छोड़ दिया जाएगा।

एनईपी 2020 आरटीई अधिनियम पर चुप है और कानूनी समर्थन के बिना शिक्षा का सार्वभौमिकरण हासिल नहीं किया जाएगा: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को आरटीई से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कानूनी तौर पर केंद्र/राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। जैसा कि आरटीई फोरम ने एक बयान में कहा, "अंतिम नीति 3-18 साल तक स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करती है, बिना इसे कानूनी अधिकार बनाए। इसलिए इसे वास्तविकता बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोई अनिवार्य तंत्र नहीं है। आरटीई अधिनियम के बिना, सार्वभौमिकरण बहुत कठिन होगा।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा, अकादमिक अध्ययन पर जोर देने के साथ, अक्सर ऐसे स्नातक तैयार करती है जिनकी आय बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। देश के सभी नागरिकों को उच्च शिक्षा में शामिल करने के लिए जीईआर विकसित करना राष्ट्रीय सरकारी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, पहुंच में सुधार और निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रावधान का विस्तार करने और साथ ही सख्त गुणवत्ता नियंत्रण नियंत्रण के साथ नई नीतियां बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में। मुफ्त शिपिंग और छात्रवृत्ति के आधार पर पात्रता को बढ़ावा देकर, खुफिया के सदस्यों के रूप में उन्नत और प्रगतिशील अनुसंधान कलाकारों के साथ-साथ नियामक दृष्टिकोण के आधार पर प्रमाणित नेताओं और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्व-घोषित प्रगति के आधार पर वार्षिक प्राधिकरण के माध्यम से सख्त गुणवत्ता निगरानी। निगरानी, एनईपी-2020 को 2030 तक अपने लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है। निचले कॉलेजों के वर्तमान नाम वाले सभी तृतीयक संस्थान विकसित होंगे क्योंकि निजी कॉलेजों में कई संकाय हैं जो उनके नाम पर सशक्त हैं या उनके अधिकार क्षेत्र के तहत मेजबान विश्वविद्यालय बन जाते हैं। निष्पक्ष एजेंसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 5, May-June, 2024
Available online : https://sijarah.com/

बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक और मानव विज्ञान के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगी। एचई कार्यक्रम खुद को मुख्य विषयों और विषय विषयों और सभी विषयों की पसंद की स्वतंत्रता के लिए एक छात्र- केंद्रित दृष्टिकोण में बदल देगा। संकाय के सदस्य किसी दिए गए नीति ढांचे के भीतर पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली, शिक्षण और मूल्यांकन मॉडल की स्वतंत्र पसंद भी प्राप्त करते हैं। ये परिवर्तन 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में शुरू होंगे और 2030 तक जारी रहेंगे जब परिवर्तन का पहला स्तर अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।

संदर्भ

- कुमार, के. (2005). 21वीं सदी की शुरुआत में शिक्षा की गुणवत्ता: भारत से सबक। भारतीय शैक्षिक समीक्षा
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf 10/08/2020 को संदर्भित।
- वेंकटेश्वरलू एनईपी 2020 का एक आलोचनात्मक अध्ययन: मुद्दे, दृष्टिकोण, चुनौतियां, अवसर और आलोचना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च
- योजना पत्रिका अन्य पेपर लेख